राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 875/2016

लिब्रा इंडिया, प्रबंध न्यासी, बलजिंदर सिंह संधू पुत्र श्री एच.एस. संधू, आयु 40 वर्ष, निवासी ए-163, अजीत कॉलोनी, सर्किट हाउस के सामने, जोधपुर के माध्यम से।

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. निदेशक (वायु-1), रक्षा मंत्रालय, वायु मुख्यालय (वीबी), रफी मार्ग, नई दिल्ली।
3. निदेशक, परिचालन वायु यातायात सेवा, वायु मुख्यालय (वीबी), रफी मार्ग, नई दिल्ली।
4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, विमानपत्तन निदेशक, सिविल हवाई अड्डा, जोधपुर के माध्यम से।
5. राजस्थान राज्य, सचिव, नागर विमानन विभाग सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
6. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, सचिव के माध्यम से।
7. नगर निगम, जोधपुर, आयुक्त के माध्यम से।
8. जिला कलक्टर, जोधपुर (राज)
9. एयर इंडिया लिमिटेड, मुख्य प्रबंध निदेशक, एयरलाइन हाउस नंबर 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-01 के माध्यम से।
10. जेट एयरवेज, विमानपत्तन प्रबंधक, जोधपुर हवाई अड्डा, जोधपुर के माध्यम से।
11. गो एयर लाइन्स (इंडिया) लिमिटेड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रथम तल, सी-1, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर (डब्ल्यूआईसी) पांडुरंग बुढकर मार्ग, वर्ली, मुंबई (महा.)-40025 के माध्यम से।
12. इंडिगो एयरलाइंस,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेवल 1 टावर सी, ग्लोबल बिजनेस पार्क, मेहरौली गुरुग्राम रोड, गुरुग्राम (हरियाणा)-122002 के माध्यम से।
13. टाटा साई एयरलाइंस लिमिटेड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जीवन भारती टॉवर-1, 10 वा तल, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-11001 के माध्यम से।
14. स्पाइस जेट लिमिटेड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 319, उद्योग विहार, फेज-4 गुरुग्राम, (हरियाणा)-122016 के माध्यम से।

15. एयर कोस्टा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिवा योगेश्वरी एस्टेट, 59-13-34, रामचंद्र नगर, विजयवाड़ा (ए.पी.)-520008 के माध्यम से।

16. एयर एशिया इंडिया लिमिटेड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राउंड फ्लोर, अल्फा-1, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देवदेनहल्ली, बेंगलुरु (केटी)-560300 के माध्यम से।

----प्रत्युत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री अंकुर माथुर (न्यायमित्र) के साथ सुश्री श्रेष्ठा माथुर, सुश्री दिव्या बापना और हर्षवर्धन
प्रत्युत्तरदाता के लिए	:	श्री देवेश यादव, एजीसी (वीसी के माध्यम से) श्री आर.डी. रस्तोगी, वरिष्ठ अधिवक्ता और एएसजी के लिए श्री राजेश पंवार, वरिष्ठ अधिवक्ता और एएजी श्री रवींद्र पुरी, एजीसी द्वारा सहायता प्राप्त श्री विकास बालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सचिन सारस्वत द्वारा सहायता प्राप्त श्री कार्तिक सिंह लोढ़ा श्री दिलीप कवाड़िया श्री रजत दवे सुश्री अव्या गुप्ता के साथ

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी

माननीय श्री न्यायमूर्ति चंद्र प्रकाश श्रीमाली

आदेश

रिपोर्ट किए जाने योग्य

20/02/2025

थार के हृदय में, जहाँ रेत आकाश से मिलती है,
शहर विस्मृत खड़े हैं, एक तपती आह के नीचे।

पश्चिमी शहर, धूल से बंधे,
उड़ान के पंखों से वंचित, उनकी सड़कें अन्यायपूर्ण छोड़ दी गईं।

उनके जुड़ाव के सपने फीके पड़ जाते हैं, अनचाहे।
अलग-थलग और शांत, वे उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं
जब आकाश खुलेंगे, और उन्हें दूर ले जाएंगे।
विमानन की पहुँच के बिना, प्रगति ठहरी है,
रेगिस्तान फुसफुसाता है, फिर भी कोई पूरा नहीं कर सकता।
विस्मृत आशा की इस भूमि में, वे बने रहते हैं,
रेत के टीलों से बंधे, एक अंतहीन टेक में।

---

1. भारत 32,87,263 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करता है, जो बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है, जिससे यह दुनिया का 7 वां सबसे बड़ा देश बन गया है। इस विशाल देश में, लगभग 4000 शहर और कस्बे हैं। इसके अलावा, राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। यह भारत के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 10.4% है और भारत को शेष दुनिया से जोड़ने के लिए एक प्रमुख उत्तर-पश्चिमी प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

2. जोधपुर, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर और थार रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, काफी हद तक अपने भौगोलिक स्थान और बुनियादी ढांचे के अल्प विकास के कारण संपर्क और विकास के मामले में चुनौतियों का सामना करता है। यह शहर दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक के किनारे पर स्थित है, जो, हालांकि इसके प्राकृतिक आकर्षण को बढ़ाता है, लेकिन इसे प्रमुख शहरी केंद्रों से भी अलग करता है। पर्याप्त विमानन बुनियादी ढांचे की कमी इसकी संपर्क समस्याओं को और बढ़ा देती है। एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर और एक पर्यटन स्थल होने के बावजूद, जोधपुर हवाई अड्डे की क्षमता सीमित है, जिसमें प्रमुख शहरों से और उनके लिए सीधी उड़ानें कम हैं। कुशल हवाई यात्रा विकल्पों की इस कमी के कारण यह देश के अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में कम सुलभ है, जो व्यापार के साथ-साथ पर्यटन क्षमता को भी सीमित करता है। थार रेगिस्तान के पास इसकी दूरस्थ स्थिति, इन बुनियादी ढांचे के अंतराल के साथ मिलकर, इसके विकास में बाधा डालती है और इसे अधिक जुड़े हुए क्षेत्रों में देखी गई तेज प्रगति से कुछ हद तक कम जुड़ा हुआ रखा है।

3. जोधपुर न केवल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ (न्यायिक राजधानी) है, बल्कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न संस्थानों का भी घर है। हालांकि, विमानन बुनियादी ढांचे की कमी, जिसके परिणामस्वरूप खराब संपर्क है, ने इन सभी संस्थानों के प्रभावी कामकाज में बाधा डाली है, क्योंकि भारत के अन्य प्रमुख शहरों से कई प्रख्यात डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, पेशेवर और संकाय अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए जोधपुर की यात्रा करने में असमर्थ हैं।

4. भारी मन से, यह न्यायालय देखता है कि उपरोक्त केवल एक बुनियादी ढांचागत मुद्दा नहीं है; बल्कि, संबंधित विमानन योजनाकारों का शिथिल दृष्टिकोण है जिसने

नागरिकों के अनुच्छेद 21 के तहत प्रगतिशील सार्थक और गरिमापूर्ण जीवन जीने के मौलिक अधिकार के संभावित उल्लंघन के लिए द्वार खोल दिए हैं।

5. इसके अतिरिक्त, भारत एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, संविधान के भाग IV में निहित राज्य का यह कर्तव्य है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में, अनुच्छेद 38 के तहत लोगों के कल्याण को सुरक्षित करके और सामाजिक व्यवस्था की प्रभावी ढंग से रक्षा करके बढ़ावा देना जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों को सूचित करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सार्थक जीवन के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं तक उचित पहुँच सुनिश्चित करके सुरक्षित किया जा सकता है, और संपर्क यहाँ सर्वोच्च महत्व प्राप्त करता है क्योंकि यह नागरिकों को राष्ट्र और दुनिया के अन्य हिस्सों से जुड़ने में सक्षम बनाता है, और इस प्रकार अति आवश्यक शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त, यह निर्यात और आयात की सुविधा प्रदान करके उनके व्यवसायों को अन्य देशों से जोड़ने के लिए मार्ग प्रदान करके उनके आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है, जिससे व्यापार की सुगमता में सहायता मिलती है।

6. उपरोक्त संवैधानिक निर्देश और लगातार परमादेश के मौजूद होने के बावजूद, विमानन नीति और इसमें शामिल हितधारकों की उदासीन प्रतिक्रिया ने वे परिणाम प्रदान नहीं किए हैं जो एक आम आदमी द्वारा वांछित हैं। यह जनहित याचिका एक उड़ान या दूसरी उड़ान के बारे में नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के समग्र विकास के बारे में है, एक विशाल क्षेत्र जहाँ एक आम आदमी को राज्य की राजधानी या राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ने की आवश्यकता होने पर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है।

7. यह जनहित याचिका पिछले 9 वर्षों से लंबित है, जो रणनीतिक रक्षा क्षेत्र, आम आदमी की सुविधा, संस्थागत विकास, पर्यटन विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र विकास, शैक्षिक विकास, पेशेवर विकास और संबंधित क्षेत्रों में सुपर-स्पेशियलिटी की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, जो अन्य कारकों के साथ-साथ विमानन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग करता है, ताकि क्षेत्र के समग्र विकास को एक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।

8. यह न्यायालय नोट करता है कि 16.04.2024 को, निर्देशों पर, श्री आर.डी. रस्तोगी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता ने बयान दिया था कि नए टर्मिनल भवन का निर्माण चल रहा है और इसके मार्च, 2025 तक पूर्ण संचालन के लिए पूरा होने की उम्मीद थी, जिससे हवाई अड्डे को यात्री यातायात को अधिक कुशलता से संभालने में सक्षम बनाया जा सके।

9. उपरोक्त के बारे में पूछे जाने पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता की सहायता करने वाले विद्वान अधिवक्ता निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं कि दी गई परिस्थितियों में मार्च, 2025 की समयरेखा संभव नहीं होगी, लेकिन वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि मौखिक निर्देशों पर उन्हें बताया गया है कि विचाराधीन कार्य निश्चित रूप से अक्टूबर, 2025 तक पूरा हो जाएगा। वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि लगभग 75% कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

10. यह न्यायालय यह भी पाता है कि 13 टैक्सी स्टैंड जो विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता द्वारा दी गई समयरेखा के अनुसार मार्च, 2025 तक चालू होने थे, पूरे हो चुके हैं। यह न्यायालय पाता है कि सीआईएसएफ कर्मियों के संबंध में, श्री दिलीप कवाड़िया कहते हैं कि 197 सीआईएसएफ कर्मी पहले से ही तैनात हैं और हवाई अड्डे पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और उनके कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित अन्य सभी मुद्दों पर काम किया जा रहा है।

11. श्री राजेश पंवार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता दोहराते हैं कि वैट रियायतें की पेशकश की जा रही है और प्रस्तुत करते हैं कि वह अन्य प्रगतिशील राज्यों द्वारा दी गई रियायतों की तुलना करेंगे और आकलन करेंगे कि क्या विमानन प्राधिकरण द्वारा उक्त परिसर में प्रोत्साहन-वार कोई और छूट प्रदान की जा सकती है।

12. जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री रजत दवे प्रस्तुत करते हैं कि ग्राम खारदा रणधीर की 25 बीघा भूमि जो खसरा संख्या 89 में आती है, को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को आवासीय मूल्य के 50% पर आवंटित करने का प्रस्ताव था। हालाँकि, उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है और इसे उन्हें सौंपा नहीं गया है और इस न्यायालय के निर्देशानुसार, विचाराधीन भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी गई है। वह स्वीकार करते हैं कि यह हवाई अड्डे से लगभग 6 से 8 किलोमीटर दूर है।

13. श्री विकास बालिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सचिन सारस्वत और श्री कार्तिक सिंह लोढ़ा द्वारा सहायता प्राप्त, जो क्रमशः इंडिगो एयरलाइंस और एयर इंडिया एयरलाइंस के लिए पेश हो रहे हैं; प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने इस स्तर पर व्यवहार्यता की जाँच की है और यह प्रस्तुत करने के लिए निर्देश प्राप्त हैं कि इस मोड़ पर उड़ानों में वृद्धि, व्यवहार्य नहीं होगी, हालाँकि एक आशावादी नोट पर वे प्रस्तुत करते हैं कि एयरलाइंस व्यवहार्यता का पुनर्मूल्यांकन करना जारी रखेगी और यदि, किसी भी समय, व्यवहार्यता के स्पेक्ट्रम में कोई बदलाव होता है, तो उसे कार्यान्वित किया जाएगा।

14. श्री अंकुर माथुर, विद्वान न्यायमित्र, सुश्री श्रेष्ठा माथुर द्वारा सहायता प्राप्त, प्रस्तुत करते हैं कि अलायंस केंद्र सरकार के नियंत्रण में एक एयरलाइन है और यदि निर्देश दिया जाता है, तो वे आवश्यक उड़ानें प्रदान कर सकते हैं। श्री माथुर प्रस्तुत करते हैं कि केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी एयरलाइनों को विचाराधीन अंतराल को भरने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया जा सकता है।

15. यह न्यायालय पाता है कि 27.08.2024 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया था, जिसमें यह देखते हुए कि वर्तमान जनहित याचिका 2016 से लंबित है और 'निगरानी घंटे' (गर्मियों के साथ-साथ सर्दियों) को शाम और रात के परिचालन में बढ़ाया जाना था और रात के परिचालन भी शुरू किए जाएंगे, यह नोट किया गया था और विभिन्न एयरलाइनों को डार्क घंटों का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए निर्देश भी दिए गए थे जो लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा क्योंकि विचाराधीन हवाई अड्डे पर उसके लिए सुविधाएं नहीं थीं।

16. यह न्यायालय यह भी नोट करता है कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालिया ने एक उदाहरण दिया कि प्रत्युत्तरदाताओं की समयरेखा के कारण यदि निजी एयरलाइनों ने मार्च, 2025 तक आवश्यक विस्तार के लिए सहमति व्यक्त की होती, तो इससे निश्चित रूप से एयरलाइनों को गंभीर वित्तीय झटका लगता और इस प्रकार, बुनियादी ढांचे की योजना और आकलन को उनके द्वारा विस्तार के परिचालन से पहले होना चाहिए।

17. यह न्यायालय पाता है कि विमानन क्षेत्र में सुविधाओं की निराशाजनक स्थितियों के संबंध में वर्तमान स्थिति से संबंधित मुद्दा बुनियादी ढांचे के विकास की धीमी गति, उक्त उद्देश्य के लिए समयसीमा के विस्तार (एक के बाद एक) और ठोस निर्णयों की कमी के कारण है।

18. यह न्यायालय आम नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाओं के बारे में भी चिंतित है क्योंकि पहले के समय में विमानन उद्योग एक विशिष्ट उद्योग था जो केवल उच्च वर्ग की जरूरतों को पूरा करता था लेकिन आज आधुनिक समय में, वैश्वीकरण के बाद जहाँ सभी देश आर्थिक रूप से एकीकृत हो गए हैं, आर्थिक विकास, वित्तीय, संस्थागत, पेशेवर और सुपर-स्पेशियलिटी संभावनाओं और अन्य मार्गों का विस्तार, आजीविका के अधिकार के साथ, हवाई आवागमन की सुगमता पर निर्भर करता है।

19. हालाँकि, प्रत्युत्तरदाताओं द्वारा बार-बार आश्वासन दिए गए हैं लेकिन जमीनी स्तर पर, इस लगातार परमादेश के पिछले 9 वर्षों से, कोई वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है।

20. हालाँकि, न्याय के हित में, इस न्यायालय द्वारा पारित पिछले आदेशों सहित स्थिति का समग्र दृष्टिकोण रखते हुए, निम्नलिखित निर्देश पारित किए जाते हैं: -

(i) टर्मिनल भवन जिसकी समयरेखा मार्च, 2025 थी और जो विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता के मौखिक आश्वासन के साथ पूरा होने से बहुत दूर है कि इसके अक्टूबर, 2025 तक पूरा होने की संभावना है, को एक शपथ पत्र के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है जिस पर भारत सरकार के सचिव, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जबकि प्रत्युत्तरदाताओं की मार्च, 2025 की समयरेखा का पालन करने में विफलता के कारणों को दिया जाएगा और नागरिक हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को अक्टूबर, 2025 तक कैसे पूरा करने का प्रस्ताव है, इसके बारे में सभी विवरण भी प्रदान करेंगे।

(ii) उपरोक्त शपथ पत्र में 13 टैक्सी स्टैंडों की जानकारी/स्थिति भी शामिल होगी जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पूरे हो चुके हैं और परिचालन के लिए तैयार हैं।

(iii) महानिदेशक, सीआईएसएफ, नई दिल्ली स्थायी आवासीय/आवास सुविधाओं के पूरा होने के संबंध में एक शपथ पत्र दाखिल करेंगे कि प्रत्युत्तरदाताओं की क्या योजना है और इस तरह के बुनियादी ढांचे की कितनी दूर तक योजना बनाई जा रही है और वे इसे कैसे निष्पादित करने का इरादा रखते हैं।

(iv) महानिदेशक, सीआईएसएफ को अपनी वर्तमान तैनाती योजना देने की आवश्यकता होगी जिसमें इस न्यायालय को पर्याप्त तैनाती के संबंध में संतुष्ट करने के लिए यह विवरण शामिल होगा कि वे सुबह 5:00 बजे से रात 9:30 बजे तक कर्तव्यों के लिए अपने 197 कर्मियों को कैसे प्रबंधित कर रहे हैं।

(v) श्री राजेश पंवार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता जिम्मेदार अधिकारियों के साथ मिलकर भारत संघ के प्रगतिशील राज्यों द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों का आकलन करेंगे और विचार करेंगे कि क्या निजी एयरलाइनों की व्यवहार्यता और प्रोत्साहन के उद्देश्य से विचाराधीन विमानन क्षेत्र में विमानन उद्योग को ऐसे प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकते हैं। ऐसे आकलन को शपथ पत्र के रूप में तैयार किया जाना और इस न्यायालय के समक्ष पुन: प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

21. न्यायमित्र अन्य राज्यों की तुलना में विमानन क्षेत्र के विकास के संबंध में पहले से सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध जानकारी के अनुसार तुलनात्मक आकलन भी प्रदान करेंगे और अन्य राज्यों के पहले तीन महत्वपूर्ण हवाई अड्डों की सुविधाओं के बारे में जानकारी भी देंगे।

22. श्री दवे, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त का एक शपथ पत्र दाखिल करेंगे कि वे भविष्य के विस्तार और विकास के उद्देश्य से नागरिक हवाई अड्डे को और अधिक भूमि कैसे प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे शपथ पत्र में सुझाव, अन्वेषण और संभावित भूमि शामिल होगी जो राज्य भूमि बैंक/किसी भी प्रकार की अधिग्रहण योजना द्वारा दी जा सकती है जिसे जेडीए हवाई अड्डे पर कार्गो और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से प्रस्तावित कर सकता है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के साथ पहले प्रस्तावित 25 बीघा भूमि के संबंध में यथास्थिति जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए रखी जाएगी।

23. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता को आवश्यक निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है कि पश्चिमी राजस्थान जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विमानन नीति कैसे मौजूद है और विमानन मंत्रालय दूर-दराज के क्षेत्रों को कैसे एकीकृत करने का प्रस्ताव करता है जिनमें विमानन क्षेत्र के संबंध में कुशल संपर्क नहीं है, ऐसी जानकारी भारत सरकार के सचिव, नागर विमानन मंत्रालय के शपथ पत्र के तहत दायर की जाएगी, जिसे इस आदेश के परिच्छेद 20 में पहले ही इस न्यायालय के समक्ष रखने का निर्देश दिया जा चुका है। विचाराधीन नीति अपने शपथ पत्र के माध्यम से रोड मैप को इंगित करेगी जो विमानन मंत्रालय के पास पश्चिमी राजस्थान तक विमानन की पहुंच के विकास के लिए मौजूद है।

24. इस स्तर पर, न्यायमित्र प्रस्तुत करते हैं कि विमानन उद्योग देश के पश्चिमी भाग के लिए किसी भी विशेष योजना का विवरण भी प्रदान कर सकता है जैसा कि उनके पास देश के पूर्वी भाग के लिए हो सकता है जो दूर-दराज का है और कुशल विमानन सुविधाओं द्वारा जुड़े रहने की आवश्यकता है। पश्चिमी राजस्थान पूरे देश के लिए ऊर्जा क्षेत्र बनता जा रहा है और ऐसे शपथ पत्र दाखिल करते समय अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।

25. यह न्यायालय निर्देश देता है कि पश्चिमी राजस्थान में विमानन क्षेत्र के विकास के संबंध में ऐसी कोई नीति मौजूद है या नहीं, इस तथ्य के संबंध में सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (नागर विमानन), राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा एक शपथ पत्र दायर किया जाए।

26. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता एलायंस एयरलाइंस को अपनी सेवाओं को बढ़ाने का निर्देश दिया जा सकता है या नहीं, यह पता लगाने के लिए निर्देश भी लेंगे क्योंकि इसकी पश्चिमी राजस्थान में कोई उड़ान नहीं है।

27. मामले को ***17.03.2025*** को सूचीबद्ध करें।

(चंद्र प्रकाश श्रीमाली), न्यायमूर्ति (डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी), न्यायमूर्ति

14-हनुमान/-

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

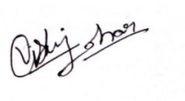

एडवोकेट विष्णु जांगिड़